Nai Dunia (Indore), 2nd September 2023, Nai Dunia City, P – I

आइआइटी व मध्य प्रदेश सरकार के बीच महत्वपूर्ण एमओयू

राज्य के कालेजों के बीटेक छात्र आइआइटी इंदौर से कर सकेंगे अंतिम वर्ष की पढ़ाई

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) इंदौर ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग, शैक्षिक अवसरों और छात्र गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के साथ आइआइटी इंदौर ने किया है। साथ ही विद्या समागम कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल सहित सभी स्वायत्त सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों के छात्रों को आइआइटी इंदौर से बीटेक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा छात्रों को अत्याधुनिक अनुसंधान में आइआइटी के संकायों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर आइआइटी के निदेशक प्रो. सुहास जोशी और मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता पांच वर्षों तक वैध रहेगा।

प्रो. सुहास जोशी ने कहा कि प्री-फाइनल वर्ष में पढ़ने वाले सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग और धातुकर्म में कालेजों के मेधावी बीटेक छात्र, जिनका कोई पिछले सेमेस्टर से बैकलाग नहीं है, इससे उन्हें लाभ होगा। हमारी एक चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें आइआइटी इंदौर द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्यक्रम के लिए चयनित छात्र सातवें सेमेस्टर से आनलाइन मोड में अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। छात्र मार्गदर्शन और प्रोजेक्ट कार्य के लिए छुट्टियों के दौरान आइआइटी इंदौर आ सकते हैं। वे आठवें सेमेस्टर में आइआइटी में शामिल होंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। साथ ही कालेज की आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन किए गए प्रोजेक्टों और पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का मूल्यांकन आइआइटी की शैक्षणिक नीति के अनुसार किया जाएगा।

आइआइटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास जोशी और मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए। • सौजन्य